**डी. आर. डी. ओ. में वैज्ञानिकों/कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निर्धारण**

435. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमान डी. आर डी. ओ. और रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण, डी. आर. डी ओ. के वैज्ञानिक और कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनर्निर्धारण नहीं किया जा सका था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है, ताकि वैज्ञानिकों को उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप वेतनमान मिल सकें ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. राजा रमन्ना)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास**

436. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है, जिनका पेक्सेम–I और पेक्सेम-II योजनाओं के तहत भारतीय और योजनाओं के तहत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई सहायता से मध्य प्रदेश में अब तक पुनर्वास किया गया है, ;

(ख) इस समय राज्य में ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है जिनका अब तक पुनर्वास नहीं किया गया है ; और

(ग) शेष भूतपूर्व सैनिकों का कब तक पुनर्वास कर दिए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. राजा रमन्ना) : (क) और (ख) "पेक्सेम" योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कार्मिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोज़गार प्राप्त करने में और उन्हें अपना काम धंधा शुरु करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का इस योजना से संबंध नहीं है । "पेक्सेम–I" और "पेक्सेम–II" के नाम से अलग-अलग कोई योजना नहीं है ।

सेमफेक्स–I और सेमफेक्स–II नामक योजनाएं हैं जो क्रमशः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से चलाई गई हैं । ये योजनाएं भूतपूर्व सैनिकों को अपने निजी काम धंधे खोलने के लिए प्रोत्साहित करती है । सेमफेक्स–I योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए आवेदन संबंधित राज्य वित्तीय निगम को पेश करने होते हैं । 31 दिसम्बर, 1989 तक, मध्य प्रदेश के 230 भूतपूर्व सैनिकों ने सेमफेक्स–I योजना के अन्तर्गत, अपने निजी उद्योग-धंधों के लिए मध्य प्रदेश राज्य वित्तीय निगम से सहायता मांगी थी । इनमें से अब तक 91 भूतपूर्व सैनिकों को सहायता की जा चुकी है और 124 भूतपूर्व सैनिकों के आवेदन नामंजूर कर दिए हैं । शेष 15 आवेदनों की मध्य प्रदेश राज्य वित्तीय निगम द्वारा जांच की जा रही है ।

31 दिसम्बर, 1989 तक मध्य प्रदेश में सेमफेक्स–II के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य वित्तीय निगम द्वारा, पात्रता के मानदण्डों के अनुसार आवेदनों की जांच करने और परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता का पता लगाने के पश्चात् सेमफेक्स–II योजना के अन्तर्गत ऋण मंजूर किए जाते हैं । सामान्यतः आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए लगभग 3 से 6 महीने लगते हैं ।

**Pollution control tests in Delhi**

437. SHRI SURENDRA SINGH THAKUR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have launched a mobile pollution control test on motor vehicles plying in Delhi to ensure minimum pollution level by these vehicles;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it is also a fact that pollution control test is being carried out by Transport Authorities on mobile laboratories, and also by fixed units of Department of Environment at different places;

(d) if so, in case of difference of opinion which test prevails;

(e) whether it has come to the notice of the Government that pollution control certificate issued by laboratories has not been accepted by the mobile test units; and

(f) if so, what steps have been taken by Government to check the harassment of the vehicle owners by mobile units of Transport Department?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) Yes, Sir.

(b) The Directorate of Transport have 12 mobile teams to conduct pollution checks on vehicles plying in Delhi in order to make the public aware of the pollution control provisions being enforced from 1.3.1990. Since the introduction of the Rule 115(2) of Central Motor Vehicle Rules, 1989 from 1.3.1990, the Directorate of Transport has checked about 57,500 petrol-driven vehicles through the mobile teams till 26.4.90. Out of these approximately 21,500 vehicle owners have been issued warnings, slips for non-compliance of standards prescribed. In addition, a prosecution drive has been launched in the month of April, 1990 against polluting vehicles of the DTC and other Government Departments and 230 vehicles have been prosecuted for non-compliance of pollution standards in accordance with the provisions of the Motor (Vehicles) Act, 1988.

(c) The Directorate of Transport have in all 7 static and 12 mobile units to carry out pollution checks on various types of vehicles in Delhi. All vehicles which undergo vehicle checks, are issued a certificate. The Department of Environment and Forests has no units to carry out checks on vehicular emission.

(d) Does not arise.

(e) No such report has been received.

(f) Does not arise.

**Implementation of graded promotion in Kendriya Vidyalaya Sangathan**

438. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of the proposition graded promotion, suggested by the Kendriya Vidyalaya Sangathan Review Committee;

(b) whether it has been accepted by Government; and

(c) if so, the details thereof and if not reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) to (c) The Kendriya Vidyalaya Sangathan Review Committee has made no recommendation about graded promotions. However, it did recommend that Kendriya Vidyalaya Sangathan should adopt a faculty development programme linked to promotions based on earning of credits by teachers in both academic and professional work.

The recommendations of the Review Committee were examined by an Empowered Committee constituted by the Government. Together with the advice of the Empowered Committee, the recommendations of the Review Committee have been sent to the Kendriya Vidyalaya Sangathan for the purpose of follow-up action, as per rules. Kendriya Vidyalaya San-